पाकिस्तानी और हमारे सैनिकों के बीच नियंत्रण रेखा पर गोली बारी होना एक सामान्य घटना है क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक प्राय: अकारण गोलाबारी करते रहते हैं ।

(ग) उक्त मुठभेड़ों में मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के परिवार उदारीकृत पेंशन पाने के हकदार हैं । इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है ।

(1) सैन्य कार्मिक द्वारा लिए गए अंतिम वेतन की दर पर उसकी मृत्यु होने अथवा उसके पात्र न रह जाने तक उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन ।

(2) मृत्यु उपदान नीचे दिए अनुसार होगा :

| | | |
|---|---|---|
| * (कक) | एक वर्ष से कम की सेवा | — 2 माह का वेतन |
| (कख) | 1 से 5 वर्ष की सेवा | — 6 माह का वेतन |
| (कग) | 5 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम की सेवा | — 12 माह का वेतन |
| (कघ) | 20 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा | — हर एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक महीने का वेतन परंतु इस निमित 33 महीने का वेतन |

* उदारीकृत पेंशन का हिसाब लगाने के लिए वास्तविक सेवा में पांच वर्ष का और लाभ दिया जाता है ।

अथवा एक लाख रुपये की राशि, इनमें से जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा ।

(3) जे सी ओ और अन्य रैंकों के लिए 450 रुपये से 1600 रुपये तक तथा रैंक के आधार पर अफसरों के लिए 2000 रुपये से 1600 रुपये तक की निर्धारित दरों के अनुसार परिवार उपदान ।

**Set-back in defence preparedness**

49. SHRI ANANT RAM JAISWAL : SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of the loss of the Soviet credit card and shortage of resources, various areas of defence such as maintenance of fleet, upgradation of various defence areas besides development of high technological system and air preparedness are suffering a set-back ;

(b) if so, what are the details thereof stating the implications in the defence preparedness due to non-implementation of various schemes under taken by Government ; and

(c) the manner in which Government propose to overcome the impediments in defence preparedness ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c) There are continuing arringements for credit for defence-related supplies from Russia. Government is taking all necessary measures to ensure that our defence requirements are fully met and there is no setback or reduction in defence preparedness.